[श्री जी. वी. एल. नरसिहा राव]

कि जो राज्य सरकारें केन्द्र के इस कानून को प्रदेशों में अमल में लाएंगी, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। केन्द्र के तीन agricultural Acts को..

श्री उपसभापति: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री जी.वी.एल.नरसिंहा राव : मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार किस प्रकार का प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है?

श्री परशोत्तम रुपाला: उपसभापति महोदय, मैं माननीय नरसिंहा राव जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह सवाल ग्रामीण हाटों को डेवलप करने के संबंध में है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, वह APMCs के संबंध में है। मैं उनके बारे में भी आपको विस्तार से बता सकता हूं। इन तीनों एक्ट्स को लागू करने के लिए हम राज्य सरकारों के साथ pursue कर रहे हैं।

श्री उपसभापति: प्रश्न संख्या 63, डा. अनिल अग्रवाल।

Damage of crops due to locust attack

*63. DR. ANIL AGRAWAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that locusts have damaged crops across the country during the last two years and till now, if so, the details thereof, State-wise;

(b) the State-wise details of Total loss of crops due to attack of locusts during the last two years; and

(c) the compensation paid by Government to the affected farmers whose crops have been damaged?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI KAILASH CHOUDHARY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) During financial year 2018-19, there was no locust attack in India.

During financial year 2019-20, Gujarat State Government has reported that locust has damaged crops and the Total estimated damaged crop area is 18,727 hectares, out of which damage of 33% and more is estimated in 13,881 hectares.

Rajasthan State Government has reported that the Total affected area due to locust attack during 2019-20 in the State is 1,49,821 hectares, out of which Total damaged crop area of 33% and more is 1,34,959 hectares.

Punjab State Government has reported that a small/little group of locust adults were spotted in few patches, which have been adequately dealt with. Till date no loss to any crop has been reported in this Rabi season 2019-20.

Haryana State Government has reported that in January, 2020, the Locust appeared in Rajasthan adjoining villages of Sirsa district. No damage of crops has been reported.

(c) State Government of Gujarat has reported that, they have done the primary assessment of the crop losses due to locust attack. Relief package is announced where crop loss is 33% and more for paying relief to the farmers of affected districts in the State. Assistance of ₹13,500/- per hectare from State Disaster Response Fund and additional ₹5000/- per hectare from State budget will be provided for maximum up to 2 hectares to affected farmers. Total provision for this relief package is ₹ 32.76 crore for approximate 11,230 farmers. The payment to the affected farmers is in progress.

State Government of Rajasthan has reported that Girdavari (assessment by Revenue Department) of crop have been conducted by State Government about damage occurred due to locust attack. A Total budget of ₹ 90.20 crore has been allotted under State Disaster Response Fund for payment to farmers. Out of this, ₹ 86.21 crore has been paid to 54,150 farmers.

प्रश्न संख्या 63

डा. अनिल अग्रवाल: माननीय उपसभापति जी, लगभग प्रत्येक वर्ष टिड्डियों के हमले से फसलों का काफी नुकसान होता है, जिससे किसान भाइयों को काफी आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का नुकसान भविष्य में न हो, इसके लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने टिड्डियों के बारे में जो प्रश्न किया है कि लगातार हर वर्ष टिड्डियों से नुकसान होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टिड्डियां आई हैं, ये लगभग 26 वर्ष बाद भारत में आई हैं। ये 1993 में आई थीं, उसके बाद में नहीं आईं। कभी थोड़ी बहुत आईं, तो उनको कंट्रोल कर दिया गया।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, जवाब ब्रीफली दें।

श्री कैलाश चौधरी: ये अभी लगभग सभी जगह नियंत्रण में हैं और हमने आने वाले समय के लिए प्लानिंग की है। हमने लगभग 60 मशीनें और परचेज की हैं, जो जल्दी आ जाएंगी।

[श्री कैलाश चौधरी]

भविष्य में अगर हेलिकॉप्टर के माध्यम से एयर स्प्रे करने की आवश्यकता होगी, तो हम वह भी करेंगे। किसानों के लिए जो भी संभव होगा, वह किया जाएगा। अभी टिड्डियां पूर्ण रूप से नियंत्रण में हैं और अगर भविष्य में उनके आने का कोई खतरा होगा, तो हम उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं।

डा. अनिल अग्रवाल: महोदय, इस वर्ष टिड्डियों के हमले से हुए फसलों के नुकसान का आकलन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया गया है। क्या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा भी टिड्डियों के हमले से हुए नुकसान के लिए कोई केंद्रीय दल भेजा गया है? यदि हां, तो केंद्रीय दल का आकलन क्या है?

श्री कैलाश चौधरी: महोदय, किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर केंद्रीय दल भी वहां गया है और मैं स्वयं वहां गया हूं। मैंने खुद वहां जाकर स्प्रे करके और गाड़ी चलाकर देखा कि किस तरह से टिड्डी को मारा जाता है। यह मैंने स्वयं गाड़ी चलाकर किया है। किसानों के लिए मुआवज़े की जो बात है, SDRF फंड का जो पैसा है, वह राज्य सरकारों को दिया है और राज्य सरकारों ने वहां किसानों को उसकी... जैसा कि गुजरात की बात करें, तो गुजरात के अंदर हर किसान को जो 13,000 रुपये प्रति दो हैक्टेयर के अंदर दिया जाना चाहिए था, उसके अलावा जोड़कर 5,000 रुपये और किसानों को दिए हैं। इसी तरह राजस्थान के अंदर भी...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, जवाब ब्रीफली दें, हमने बहुत सारे क्वेश्चन्स और लेने हैं।

श्री कैलाश चौधरी: किसानों के पास लगभग 86 करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं।

श्री उपसभापति: माननीय अमर शंकर साबले जी, आज आपका जन्मदिन भी है, आपको शुभकामनाएं। आप अपना सवाल पूछें।

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): धन्यवाद, उपसभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फसलों पर होने वाला हमला हो या जीव-जन्तु का हमला हो या नैसर्गिक विपत्ति हो, इसकी देखभाल और इन्सपेक्शन करने के लिए ड्रोन, सेटेलाइट, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस, डाटा एनेलेटिक्स, ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या सरकार कार्य करने का विचार कर सकती है?

श्री कैलाश चौधरी: मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि हम भविष्य के अंदर इस तरह की प्लानिंग करे रहे हैं। जैसे जो स्प्रे होगा, हम वर्तमान में मशीन से स्प्रे करते हैं, उसके लिए भी हमने मशीनें खरीदी हैं, जो कि नई टेक्नोलॉजी की हैं। इसके साथ ही हमने इस बार भी ड्रोन के द्वारा इसका प्रयोग किया है और ड्रोन के माध्यम से हमने कलैक्टर से परमिशन लेकर, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए परमिशन लेकर ड्रोन के माध्यम से भी टिड्डियों

को वहां पर मारने का काम किया। हम भविष्य के अंदर भी ड्रोन और हेलिकॉप्टर के द्वारा हवाई स्प्रे करके, जो भी नई तकनीकें होंगी, उनके द्वारा इनको नियंत्रित किया जाएगा।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, the most effective and readily available way to counter the locust swarms is to use the lethal pesticides, such as, organophosphate, OPS, which eventually leach into the desert water bodies as well as the next crop. Therefore, what steps the Government is taking to find out and implement other viable ways to counter the locust attack?

श्री कैलाश चौधरी: वर्तमान में जो पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, वह Meratheon-96 डाला जा रहा है। जिस तरह से cyanide का असर होता है, वैसा ही अगर उसके ऊपर पंख में लग जाता है, तो उसका उतना ही असर होता है कि उसको मरना ही होता है। इस समय इसका प्रयोग सरकार के द्वारा किया जा रहा है और साथ ही किसानों को भी इसके बारे में स्प्रे अलग से दिया जाता है, तो उस स्प्रे से किसान की फसल को भी नुकसान नहीं होता है। उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टिड्डियां वहां से अफगानिस्तान के रास्ते, अफ्रीका से यहां आती हैं, उन्हें हमने नियंत्रित कर लिया है। ये इस बार सिर्फ पांच जिलों से आगे नहीं बढ़ पाई हैं और उसको हमने कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से वे आगे बंगलादेश तक नहीं पहुंच पाई हैं, अन्यथा वह बंगलादेश तक पहुंच सकती थी।

श्री उपसभापति: कृपया ब्रीफ में बोलिए। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन्स लेने हैं। श्री ओम प्रकाश माथुर जी। माथुर जी, आपका सवाल बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश माथुर (राजस्थान): सर, यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। जो पेस्टिसाइड का स्प्रे हो रहा है, उसमें भी मिलावट हो रही है। राजस्थान का किसान बहुत मजबूत है और उसने संकटों में जीना सीखा है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं एक प्रश्न मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। अभी जो टिड्डियों के अंडे हैं, यह मैं आपको बता रहा हूं कि तीन साल तक ये टिड्डियाँ चलेंगी। ये अंडे दोबारा से डेवलप न हों, इसके लिए आपको कदम उठाने होंगे। अभी आप कह रहे हैं कि हमने इनको पांच जिलों से आगे नहीं बढ़ने दिया और वहीं पर रोक लिया, लेकिन काफी भयानक, वीभत्स अत्याचार किसानों पर हुआ है। उनकी दोनों-तीनों फसलें सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। वहां पर पीने का पानी और राजस्थान का पूरा एरिया प्रभावित हो गया है, उसके लिए पुख्ता बंदोबस्त जितना होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि केन्द्र और राजस्थान सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। जो पहली बार स्प्रे हुआ, उसमें मिलावट है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको उस स्प्रे को मंगाकर देखना चाहिए कि उसमें कितनी मिलावट की गई और टिड्डियां बढ़ती गईं। अभी 100 किलोमीटर एरिया में..

श्री उपसभापति: माननीय माथुर जी, प्लीज़ सवाल पूछिए।

श्री ओम प्रकाश माथुर: सर, यह बहुत ही संवेदनशील सवाल है।

श्री उपसभापति: सारे सवाल संवेदनशील हैं।

श्री ओम प्रकाश माथुर: सर, सरकार को किसानों की ओर देखना चाहिए कि किसान की स्थिति क्या है। अगर यही महाराष्ट्र और दक्षिण में होता तो किसानों की वहां क्या स्थिति होती? इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, आप बहुत ही ब्रीफली बताइए।

श्री कैलाश चौधरी: उपसभापति महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा टिड्डियाँ आई हैं, वे पाकिस्तान के जरिए आई हैं और वे हिन्दुस्तान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले में आई हैं। अगर समय रहते, उस समय राज्य सरकार ने सहयोग किया होता, तो निश्चित रूप से इनको नियंत्रित किया जा सकता था और समय रहते इन पर कार्रवाई कर सकते थे। पेस्टिसाइड के अंदर जिस तरह की मिलावट के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो हम इसकी जांच करायेंगे कि इसमें कितनी मिलावट की है। हम भविष्य में इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि FAO के जो वरिष्ठ अधिकारी 16 जनवरी, 17 जनवरी को यहां पर आए थे, उन्होंने भी यह रिपोर्ट दी है कि वास्तव में यहां पर इनको बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया गया और केन्द्र सरकार की अच्छी प्लानिंग रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि अफ्रीका के जिन देशों के अंदर बहुत मात्रा में टिड्डियां हैं, जिस तरह से यहां पर इनको नियंत्रित किया गया है, वैसा ही डिमॉस्ट्रेशन वहां पर करने की आवश्यकता है, ताकि वहां की सरकार टिडडियों को नियंत्रित कर सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q.No. 64. The questioner is not present. Any supplementaries?

Global challenges in the manufacturing and service sectors

*64. DR. PRABHAKAR KORE: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the present environment of competitiveness in manufacturing and service sectors have to undergo a basic paradigm shift to meet the global challenges being faced by Indian exporters;

(b) whether Government proposes to implement the remaining recommendations of the Baba Kalyani report on Special Economic Zones (SEZs) to facilitate Ease of Doing Business; and